*88. [*Transferred to the 10th August*, 1987.]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 89—Shri Sukomal Sen.

*89. [*The questioner (Shri Sukomal Sen) was absent. For answer*, vide *cols.* 35 infra.]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 90.

Prices of edible oils

*90. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI:†

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there has been any spurt in the prices of edible oils in the country during the last 3 months;

(b) if so, the extent of rise and the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to check the same?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) There has been a rising trend in the prices of edible oils during the last three months.

(b) The wholesale price index of edible oils has moved up by 9.3 per cent over three months as on 11-7-1987. The main reasons are (i) lower production of edible oilseeds during the last two years (ii) lean period and (iii) delayed and wayward behaviour of monsoon.

(c) The following measures have been taken by the Government to contain the rise in the prices of edible oils:

(i) States have been advised repeatedly, even at Chief Ministers level, to take stringent action against speculators, hotrders and other antisocial elements.

(ii) The use of expeller mustard oil in the maunfacture of Vanaspati which was earlier allowed has been prohibited from 15-5-1987.

(iii) The allocation of imported edible oils under Public Distribution System and to Vanaspati industry has been increased.

(iv) Bank credit has been restricted to trade and industry of oilseeds and oils.

(v) Inspection of Vanaspati Units was intensified to ensure that all edible oils are properly used and adequate vanaspati is despatched for sale.

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी: आदरणीया, मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल उत्पादन करने वाले तेलों की कीमतें बढ़ाने के संबंध में क्या शासन से स्वीकृति प्राप्त करते हैं या नहीं ? क्या तेल उत्पादक अपने मन से तेलों के रेट बढ़ाते जाते हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत: जहां तक तेल का सवाल है, मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश में बहुत किस्म के तेल पैदा होते हैं। उनकी कीमतों पर, इंडिजनल तेल पर, कोई कंट्रोल नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। पहले गवर्नमेंट की वनस्पति पर कंट्रोल की पालिसी थी, लेकिन काफी अर्से से उसकी प्राइसेज पर कंट्रोल नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेड आयल है, जिसका हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वह गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि उसे किन दामों पर दें । यह हम सही दामों पर दे रहे हैं। आम तेल जो हमारे हिन्दुस्तान में पैदा होता है उसमें और इम्पोर्टेड आयल में बहुत फर्क है । हम ने अभी तक जो इम्पोर्टेड आयल, पी० डी० एस० के माध्यम से देते हैं, उसके दाम वही रखे हैं जो एक साल पहले थे ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chandrika Prasad Tripathi.

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : मैंने यह पूछा है कि उत्पादक अपने मन से जो चाहे, जितना चाहे बढ़ा लें इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा उनको शासन से स्वीकृति लेने के लिए बाध्य किया गया है या नहीं किया गया है?

दूसरा, यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तेल उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई व्यवस्था शासन की ओर से की जा रही है?

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा जो प्रश्न का उत्तर था उसको मैं आनरेबल मेम्बर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक हिन्दुस्तान के अंदर तेलों के उत्पादन का सवाल है, यहां जो उत्पादन करता है उस पर कन्ट्रोल का जहां तक सवाल है, जो आयल सीड्स ग्रो करता है, तेल बनाता है और फिर तेल मार्केट में बिकता है, इस पर किसी किस्म का नियंत्रण नहीं है। बल्कि भावना यह है कि अगर हिन्दुस्तान को खाने के तेलों में सेल्फ सफिसियेन्ट होना है, अपने पैरों पर खड़े होना है तो इसके लिए उत्पादकों को इन्करेज करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने कई स्टेप लिये हैं ताकि देश में ज्यादा देशी तेल पैदा हो और बाहर के तेलों पर हम निर्भर न रहें।

श्री गुलाम रसूल कार : आनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज ने अभी फरमाया कि बारिश न होने की वजह से और दूसरी कुछ और वजहों से ऐसा हुआ। आनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज को यह पता होना चाहिए कि मार्केट में आज 30 रुपये किलो तेल बिक रहा है और आम गरीब आदमी के लिए तेल खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। डालडा तो आमतौर पर मार्केट में मिलता नहीं और मिलता भी है तो वह महंगे दामों पर मिलता है। जब प्लानिंग हमारी इस किस्म की है तो हमें यह देखना चाहिए कि मुल्क में जो तेल के बीज पैदा होते हैं उनका प्रोडक्शन क्या है। क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है इसलिए हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ता है ताकि देश में इसकी कीमतें ठीक रहें। आनरेबल मिनिस्टर साहब को यह पता होना चाहिए कि आम लोगों के लिए इस वक्त खाने का तेल महंगा हो गया है और तेल खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। . . . (व्यवधान) . . .

†[شری غلام رسول کار : آنریبل منسٹر انچارج نے ابھی فرمایا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری کچھ وجہوں سے ایسا ہوا ہے - آنریبل منسٹر انچارج کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ مارکیٹ میں آج (۳۰) روپئے کلو تیل بک رہا ہے اور عام غریب آدمی کیلئے تیل خریدنا بڑا مشکل ہو گیا ہے - ڈالڈا تو عام طور پر مارکیٹ میں ملتا نہیں اور ملتا بھی ہے - تو وہ مہنگے داموں پر ملتا ہے - جب پلاننگ ہماری اس قسم کی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ملک میں جو تیل کے بیج پیدا ہوتے ہیں - ان کا پروڈکشن کیا ہے - کیونکہ ہمارا پروڈکشن کم ہے - اسلئے ہمیں باہر سے تیل منگانا پڑتا ہے - تاکہ دیش میں اسکی قیمتیں ٹھیک رہیں - آنریبل منسٹر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ عام لوگوں کیلئے اس وقت کھانے کا مال مہنگا ہو گیا ہے اور تیل خریدنا مشکل ہو گیا ہے - . . . . (مداخلت) . . . .

SHRI A.G. KULKARNI: How can you allow that, Madam? Dr. Ratnakar Pandey's name is in the list and he is here. Mr. Minister, why should you reply at all?

SHRI H.K.L. BHAGAT: If she has allowed the question, I will reply.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मैडम, मैं आनरेबल मैम्बर को बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही हैं वह मिनिस्टर को मालूम हैं। तेल के दाम, तेल की कीमतें बढ़ी हैं बहुत बढ़ी हैं। मेरे पास इसकी डिटेल भी हैं कि डिफरेंट सेन्टर पर क्या भाव हैं। पिछले तीन महीनों में मंहगाई बढ़ी है यह मैंने खुद कहा कि तेल के दाम बढ़े हैं। माननीय सदस्य ने जो यहां पर प्रश्न उठाया है, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है सरकार उस चिंता को शेयर करती है। उन्होंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में अपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को मालूम है कि देश में उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है और इस कमी को सरकार तेल को इम्पोर्ट करके पूरा करती है। यह उन्होंने खुद ही उत्तर दिया है कि सरकार इम्पोर्ट करती है। अभी भी हमारा जो एन्टीसिपेटेड प्रोडक्शन है 1986-87 को, उसके बीच में जो हमारा एन्टीसिपेटेड प्रोडक्शन और जो डिमांड है उसके बीच में जो अंतर है उसको दूर करने के लिये हमने काफी मात्रा में तेल इम्पोर्ट किया है। जितनी कमी है उसके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं। जो तेल देश में होता है मानसून की वजह से इस बार उसमें दिक्कत हुई है और जो टारगेट एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम हुआ हैं। हमने इम्पोर्ट भी बढ़ाया है और हम सिचुएशन पर नजर रखे हैं। यह जो विचार है इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी शेयर करती है। इसमें हमें बैलेंस स्थापित करना है किसान और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में। कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट हम बाहर से ज्यादा तेल मंगाकर पूरा कर सकते हैं। किसानों की आयल सीड बिके यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को करना है और किसी हद तक कंज्यूमर्स का बोझा बर्दाश्त करना है। तो इसके लिये हमको अपने किसानों को इन्करेज करना होगा। एक पालिसी बैलेंस की जाय जिसमें कल्टीवेटर और कंज्यूमर दोनों का इंटरेस्ट बैलेंस किया जाय। इसमें बोझा कंज्यूमर्स पर भी पड़ता है। मुझे इसके बारे में एन ए सिविल सप्लाई मिनिस्टर चिंता है और तेल के दामों पर नजर रखी जा रही है और जो संभव होगा वह किया जायेगा।

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी: सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण करने के लिये क्या ... (**व्यवधान**) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tripathi, I have not allowed you. The Minister will not reply to your question. Please sit down. You have already two questions.
आपने पहले दो पूछ लिये हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : सरकार कब नियन्त्रण करेगी मैं यह जानना चाहता हूं।

उपसभापति : आपने पहले पूछ लिया है इसलिए अब डा० रत्नाकर पांण्डेय जी को पूछने दीजिये। (**व्यवधान**) आपको दो पहले पूछने दिये हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीया उपसभापति महोदया, आदरणीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि राज्यों को बार-बार यहां तक कि मुख्य मंत्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे सट्टेबाजों, जमाखोरों तथा अन्य समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें तथा अन्य जो उत्तरदायी लोग हैं उनको सलाह दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी इस सलाह पर जिसमें यह कहा गया है कि सट्टेबाजों, जमाखोरों तथा अन्य समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें उन लोगों ने अब तक क्या कार्यवाही की है या नहीं की है यदि नहीं की हैं तो क्यों नहीं की है?

श्री एच० के० एल० भगत : उपसभापति महोदया, मैं माननीय रत्नाकर पाण्डेय जी को यह बताना चाहता हूं कि इस समय मेरे पास हर पत्र की तारीख है। कम से कम आठ बार मेरी तरफ से या मेरे मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर मुख्यमन्त्रियों को, यूनियन टेरीटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्ज को सेक्रेटरीज

के लेवल पर पत्र लिखे गये हैं। उन्होंने जो हम को उत्तर दिया है वह मैं अनेक्श्चर–18 में से पढ़ रहा हूं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ रेड्ज़ किये गये हैं और उनमें क्या हुआ है इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको यह आंकड़े दे सकता हूं। पर्टिकुलरली तेल के बारे में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है टोटल फिगर्ज हैं। मैंने थोड़ दिन पहले दिल्ली में फूड एण्ड एण्ड सिविल सप्लाइज़ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई थी और उसमें भी कहा था कि कड़ी कार्यवाही करें। दूसरी बात यह है कि पल्सेज़ एण्ड आयल सीड्ज़ कंट्रोल आर्डर है जिसके नीचे तेल की कुछ मात्रा स्टोर करने की इजाजत होती है। उस क्वांटिटी को जो स्टोरेज करने की इजाज़त है उसको भी हमने आधा कर दिया है ताकि ज्यादा मात्रा में वे स्टोरेज न कर सकें। इतने पत्र हमने उनको लिखे हैं। उनका कहना यह है कि हमने कार्यवाही की है। कोई भी राज्य हो सब मुख्य मंत्रियों को लिखा है। मेरे ख्याल में आठ कम्यूनिकेशस डिफरेंट टाइम्स पर भेजी गई हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी: उपसभापति महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया क्या तेल 40 रु० 50 रुपये, 70 रुपये किलो बिकेगा तब कुछ करेंगे?

श्री कल्पनाथ राय: उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसानों को इनकरेज करने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाये हैं और अगले पांच वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में तेल की कितनी खपत होगी तथा तेल के मामले में हिन्दुस्तान कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री एच० के० एल० भगत: उपसभापति महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। हमने बहुत से कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है वह है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। जो कदम उठाये गये हैं उनका ब्यौरा मेरे पास है। सात-आठ मुख्य कदम हैं जो हमने उठाये हैं। नेशनल आयल सीड्ज़ डवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है ग्राऊडनट के बारे में, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सन-फ्लावर के बारे में, इटरसीड डवलपमेंट करने के बारे में, उसके बाद स्टेट लेवल पर आयल सीड्ज़ ग्रोवर्ज कोआप्रेटिव फेडरेशंस फार्म की गई है। यह कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लिये हैं ताकि तेल का उत्पादन बढ़े और उत्पादकों को भी बेटर इनसेंटिव मिले। कई स्टेप्स हैं जैसे — better incentives to producers, fixation of minimum support price for oil-seeds and if the hon. Members want, I can state the steps which the Ministry has taken.

पांच साल का टोटल भी हमने वर्क आऊट किया है कि देश में कितनी डिमांड होगी और कितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे देश में खपत बढ़ रही है लेकिन आज भी दुनियां के मुकाबले में हमारी औसत खपत कम है। पांच साल का प्लान भी बनाया गया है कि कितना पैदा किया जाएगा। देश में स्थिति ऐसी है, हर साल प्लान बनाया जाता है। 1986–87 का प्लान हमने बनाया और मंथ टू मंथ राज्यों की रिक्वायरमेंट देख करके उनको एलोकेशन किया जाता है।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, Punjab has the potential of meeting the entire needs of the country provided due encouragement is given. I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken on the demands raised by Punjab in regard to encouraging the production of edible oils in the State particularly with reference to sunflower seed.

SHRI H.K.L. BHAGAT: If you will kindly permit let the Agriculture Minister will answer the question. Otherwise, my answer is that.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: You need not answer. This pertains to the Agriculture Ministry. Mr. Bansal, please give separate notice to the Minister of Agriculture.

श्री मीर्जा इर्शादबेग : हमारे इस सदन के एक कवि हैं उन्होंने जो कहा है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं। ये तो आज के संदर्भ में कह रहे हैं कि अब तो घर में न कोई दाल है न कोई तेल है यानी महंगाई, यह अधूरी जिंदगी का खेल है। तो इस सदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि क्या मान्यवर मंत्री जी यह जानते हैं कि जितने भी तेल उत्पादक राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और जितने भी मूंगफली उगाने वाले राज्य हैं जिनमें गुजरात का पहला नम्बर आता है, इनमें आज इतना अधिक सूखा है कि जिसकी वजह से जो क्राप है वह धरती से ऊपर नहीं आ पायी है। तेल जिस मात्रा में आपको पिछले साल तक उपलब्ध था सभावना यह है कि इस वर्ष शायद 10 प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं होगा। सवाल यह है कि देश की जनता को आज जिस भाव पर तेल उपलब्ध है आगे वह भाव बहुत अधिक हो जायेगा तो इन सभावनाओं को पहचानते हुए आगामी दिनों में तेल आयात करने के संबंध में तथा वर्तमान परिस्थिति में हदेश में जो तेल उपलब्ध है उसकी कीमतें और आगे न जाये इसके लिए मंत्रालय का क्या आयोजन है ?

श्री एच० के० एल० भगत : आनरेबुल मेम्बर ने उस स्थिति पर सरकार का ध्यान दिलाया है जो स्थिति सरकार के सामने है और उन्होंने ठीक ही कहा है कि गुजरात प्रदेश जिसमें ग्राउंडनट सबसे ज्यादा है, वहां सूखा पड़ने से काफी कठिनाई हो रही है। सरकार का ध्यान इसकी तरफ है कि आया कितना तेल मंगाया जाये और कितना नहीं मंगाया जाये। इस पर सरकार ने ध्यान रखा हुआ है इस पर विचार किया जा रहा है। दोनों बातें हैं, एक तरफ आप अनलिमिटेड इम्पोर्टेड आयल ला सकते है, उसका इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पर क्या पड़ेगा दूसरी तरफ कंज्यूमर पर बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है तो इस सारी सिचुएशन पर विचार किया जा रहा है, गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री अजीत जोगी : महोदया, जो स्थिति सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट है कि यदि हमको किसानों के हित को ध्यान में रखना है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखना है तो अभी कम कीमत पर तेल उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। केवल एक ही उपाय है कि जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उनके माध्यम से अधिक से अधिक तेल गरीब उपभोक्ताओं तक पहुचाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जितनी मांग है उसका कितना प्रतिशत तेल हम फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें से कितना वास्तव में गरीबों को मिल रहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : एक बात मैं जरा आनरेबुल मेम्बर की जानकारी के लिए साफ करना चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू : इस पर हाफ एन आवर डिसकशन दिया जाये। इसमें बहुत सारे प्रश्न है। मैं इस पर अलग से नोटिस दूंगा। इस पर हाफ एन आवर डिसकशन एलाउ किया जाये ....

(व्यवधान)

उपसभापति : उनको जवाब देने दीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए .... **(व्यवधान)** फेस्टीवल सीजन को व्यू में रखते हुए, त्यौहारों को सामने रखते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तेल की मात्रा को और बढ़ाया जा रहा है और जो आनरेबुल मेम्बर ने कहा है तो इसमें पूरी परसेंटेज तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन बाइ एण्ड लार्ज जो तेल इम्पोर्ट करते हैं वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया जा रहा है और उनका तेल बढ़ाया जा रहा है।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Madam, we want a half-an-hour discussion on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You Give notice. Question Hour is over.